

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

योजना भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़, देहरादून -248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
election09@gmail.com

फोन नं० (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स नं० (0135) - 2713724, 2712014

संख्या- 1650 /XXV - 37 / 2016 देहरादून : दिनांक 28 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

ELECTION-URGENT

- | | |
|---|---|
| 1- मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन। | 2- समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन। |
| 3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन। | 4- पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड। |
| 5- आयुक्त,
गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल। | 6- समस्त जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड। |

विषय:- विधान सभा का आगामी सामान्य निर्वाचन-2017, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के तत्काल पश्चात आदर्श आचार संहिता के विभिन्न बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही किए जाने के संबंध में आयोग के निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-437/6/1/2016-CCS दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आयोग द्वारा विधान सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात आदर्श आचार संहिता संबंधी निम्न बिन्दुओं पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही किए जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं:-

1-Defacement of property-

(a) **Defacement of Government property:-** आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 24 घण्टे के अन्दर किसी भी शासकीय कार्यालय, भवन, परिसर जिसमें राजकीय कार्यालय स्थापित हैं, आदि से सभी प्रकार के पोस्टर, पम्पलेट, बैनर, झण्डे, होर्डिंग्स, वालपेटिंग एवं कटआउट आदि हटवाए जाने होंगे।

(b) **Defacement of public property and misuse of public space:-** निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 48 घण्टे के अन्दर, विभिन्न जनसम्पत्तियों यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, एयरपोर्ट, रेलवे ब्रिज, रोडवेज, सरकारी बस, विद्युत/टेलीफोन पोल, नगरनिगम, नगरपालिका परिषद/नगरपंचायत आदि से सभी प्रकार की अनधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री यथा पोस्टर, पम्पलेट, बैनर, झण्डे, होर्डिंग्स, वालपेटिंग एवं कटआउट आदि हटवाए जाने होंगे।

(c) **Defacement of public Private property:-** निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 72 घण्टे के अन्दर, विभिन्न निजी परिसम्पत्तियों से सभी प्रकार की अनधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री हटवाई जानी होगी। सम्पत्ति विरूपरण के संबंध में समस्त जिलाधिकारियों को पूर्व में भी निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं।

2-Misuse of official vehicle :- निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 24 घण्टे के अन्दर यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी आदि के द्वारा किसी भी प्रकार के विभागीय वाहन/वाहनों का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है।

3-Advertisement at the cost of public exchequer :- निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के तत्काल पश्चात यह सुनिश्चित करना होगा कि, समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मॉस मीडिया आदि के

माध्यम से सत्तापक्ष द्वारा अपनी उपलब्धियों आदि के संदर्भ में पक्षतापूर्ण राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए किसी भी प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है। कदाचित यदि ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो इस तत्काल प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

4-Photograph of political functionary at official website:- निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के तत्काल पश्चात विभागीय/Official website से मा. मंत्रिगणों, राजनेता, राजनैतिक दलों आदि के सभी प्रकार के फोटोग्राफ एवं उपलब्धियों आदि का विवरण हटाना होगा।

5-Development / Construction related activities:- निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 72 घण्टे के अन्दर विभिन्न कार्यों के संबंध में निम्न प्रकार सूचना उपलब्ध कराई जानी नितान्त आवश्यक होगी:-

- 1- ऐसे कार्यों की सूची जो धरातल पर प्रारम्भ हो चुके हैं,
- 2- ऐसे कार्यों की सूची जो धरातल पर प्रारम्भ नहीं हुए हैं।

6-Activities for Expenditure Monitoring and enforcement of MCC:- निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्वाचन व्यय लेखों के अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्वाचन व्ययलेखा/आदर्श आचार संहिता संबंधी समस्त टीमें प्रभावी रूप से कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करेंगी।

7-Complaint Monitoring System:- निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 24 घण्टे के अन्दर शिकायत प्रकोष्ठ/कन्ट्रोल रूम भी 24X7 प्रभावी रूप से कार्य करना प्रारम्भ करेगा। इस संबंध में पूर्व में भी समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं इस हेतु दिशा-निर्देशों के अनुसार तत्काल सभी आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित करते हुए ड्यूटी रोस्टर भी तैयार कर लें।

8-IT Applications:- निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ आयोग की सभी IT Applications विभागीय वेबसाईट एवं Social Media सहित कार्य प्रारम्भ करेंगी। समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी इन सभी IT Applications के संबंध में विज्ञ हैं और आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार इनके संचालन और क्रियान्वयन के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कर लें।

9-Dissemination of information for Awareness of Voters and political parties:- निर्वाचन संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण क्रिया-कलापों, प्रक्रियाओं आदि का जनसामान्य के मध्य मतदाता शिक्षा सामग्री का सभी आवश्यक माध्यमों, रेडियो-टीवी चैनलों, सिनेमाघरों आदि से सीईओ/डीईओ/आरओ आदि के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

10-Active cooperation from Educational Institution and Civil Societies:- निर्वाचन संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण क्रिया-कलापों, प्रक्रियाओं आदि का जनसामान्य एवं अन्य हितधारकों के मध्य विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु इनके साथ निरन्तर प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाना।

11-Media Centre:- ईवीएम-वीवीपीएटी के प्रयोग तथा निर्वाचन संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में मतदाताओं, जनसामान्य-राजनैतिक दलों और अन्य हितधारकों के मध्य जनजागरुकता के लिए मीडिया सेन्टर की स्थापना।

12-MCMC/DEMC:- आयोग द्वारा तद् विषयक समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों आदि के विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण आदि हेतु शीघ्र MCMC / DEMC का गठन सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को पूर्व में भी आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं।

13-Control Room:- पूर्व में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जनपद में यथा समय सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ शिकायत निवारण-अनुश्रवणयुक्त कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाय जो 24X7 निरन्तर कार्य करेगा।

अतः आयोग के उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त विभाग/कार्यालयों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या- / XXV -37 / 2016 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि:- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य एकक, सचिवालय परिसर देहरादून को आयोग के उक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या-4 पर यथा समय अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रेषित।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

By Spl. Messenger/Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No. 437/6/1/2016-CCS

Dated: 26th December, 2016

To

1. The Cabinet Secretary,
Government of India,
Rashtrapati Bhawan,
New Delhi.
2. The Chief Secretaries to the Government of :-
 - (i) Goa, Panaji.
 - (ii) Manipur, Imphal.
 - (iii) Punjab, Chandigarh.
 - (iv) Uttar Pradesh, Lucknow.
 - (v) Uttarakhand, Dehradun.
3. The Chief Electoral Officers of :-
 - (i) Goa, Panaji.
 - (ii) Manipur, Imphal.
 - (iii) Punjab, Chandigarh.
 - (iv) Uttar Pradesh, Lucknow.
 - (v) Uttarakhand, Dehradun.

Subject: Immediate action to be taken for enforcement of Model Code of Conduct after announcement of General Elections to the Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand – regarding.

Sir/Madam,

I am directed to state that the operation of 'MODEL CODE OF CONDUCT' comes into effect with the announcement of elections by the Commission. In view of the impending general elections to the Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand, the Commission has given following directions for effective enforcement of provisions of MCC: -

1. **Defacement of property** – ECI instructions contained in letters, No. 437/6/INST/2015-CCS, dated 29th December, 2015; No. 437/6/INST/2012-CC&BE dated 18th January, 2012 and No. 3/7/2008/JS-II dated 7th October, 2008, provide for prevention of defacement of property. The Commission has directed to ensure strict compliance of its instructions and to take time bound action as prescribed below -

(a) **Defacement of Government property** - For this purpose a Government premise would include any Government office and the campus wherein the office building is situated. All wall writing, posters/papers or defacement in any other form, cutout/ hoardings, banners, flags etc., on Government property shall be removed within 24 hours from the announcement of elections.

(b) **Defacement of public property and misuse of public space**- All unauthorized political advertisement, in the form of wall writing/posters/papers or defacement in any other form, cutout/hoardings, banners, flags etc., at public property and in public space like Railway Stations, Bus Stands, Airports, Railway Bridges, Roadways, Govt. Buses, Electric/Telephone Poles, Municipal/local bodies' buildings etc., shall be removed within 48 hours from the announcement of elections by the Commission.

(c) **Defacement of private property**- All unauthorized political advertisement displayed at private property and subject to local law and Court's directions, if any, shall be removed within 72 hours from the announcement of elections by the Commission.

2. **Misuse of official vehicle**- The ECI's consolidated instructions contained in letter No.464/INST/2014/EPS, dated 10th April 2014, among other things, provides that **there shall be a total ban on use of official vehicle by any political party, candidate or any other person connected with election (except officials performing any election related official duty) for campaigning, electioneering or election related travel during elections (subject to certain exception mentioned therein).** The expression 'official vehicle' means and shall include, any vehicle used or capable of being used for the purpose of transport, whether propelled by mechanical power or otherwise and will include trucks, lorries, tempos, jeeps, cars, auto rickshaws, e-rickshaws, buses, belonging to Central Government, State Government/UT Administrations, Public Undertakings of Central/State Government, Joint Sector Undertakings of Central/State Government, Local bodies, Municipal Corporations, Marketing Boards, Cooperative Societies or any other body in which public funds, however small a portion of the total, are invested. **The CEOs/DEOs shall take necessary action for compliance of ECI instructions within 24 hrs of the announcement of the elections.**

3. **Advertisement at the cost of public exchequer** - ECI instructions contained in letters, No. 437/6/1/2014-CC&BE, dated 5th March, 2014 provides that at the cost of public exchequer

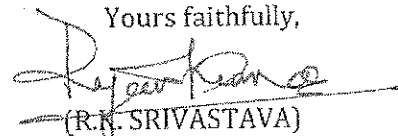
in the newspapers and other media and the misuse of official mass media during the election period for partisan coverage of political news and publicity regarding achievements with a view to furthering the prospects of the party in power shall be scrupulously avoided. No advertisements shall be issued in electronic and print media highlighting the achievements of the Govt. at the cost of public exchequer. If any advertisement has already been released for telecast/broadcast or publication in the print media, it must be ensured that the telecast/broadcast of such ads on electronic media is stopped forthwith and that no such ad is published in any newspapers, magazines, etc., i.e. in print media, from the date of announcement and it should be immediately withdrawn. **The CEOs/DEOs has to take immediate action to remove/stop any advertisement, in the print/electronic media, showing the achievements of the Government soon after the announcement of elections.**

4. **Photograph of political functionary at official website-** ECI instruction contained in letters No. 437/6/INST/2014-CC&BE dated 20th March, 2014 provides that all references of Ministers, Politicians or Political Parties available on Central/State Government's official website, shall be removed. The CEOs have to take immediate action to remove/hide the photographs of any political functionary from official websites of State department.
5. **Development/Construction related activities - Within 72 hours** of announcement of elections, the CEO/DEO shall obtain the following list of works for reference in case of validating any complaint on violation of MCC:
 - (i) List of work which has already been started on ground.
 - (ii) List of fresh work which has not started on ground.
6. **Activities for Expenditure Monitoring and enforcement of MCC -** Flying squad, FST, Video team, intensive checking for liquor/cash/contra banned drugs, flying squads of excise department to check illicit trafficking of Drug/narcotics to be immediately activated after announcement.
7. **Complaint Monitoring System -** The poll going States shall have a complaint redressal mechanism based on website and call center. The toll free number of call center is 1950. Complaints can be registered by making calls to the toll free call center numbers or on the web site. Complainants will also be informed of the action taken by SMS and by the call center. Complainants can also see the details of the action taken on their complaints. This

system should be operational within 24 hours of the announcement. All complaint should be dealt with promptly and properly. The 24X7 Control Room at the district level must be activated and sufficient deployment of manpower and other logistics be ensured in particular, round the clock personnel should be deployed in the Control Room and their duty roster must be issued to avoid any evasion or confusion.

8. **IT Applications** – All IT applications including official Website and Social Media shall be operational with the announcement.
9. **Dissemination of information for Awareness of Voters and political parties.** Publicity of major election activity would be given through CEO/DEO/RO. For this purpose, all necessary information shall be disseminated through radio, tv, cinema. Government channel to display voter education material.
10. **Active cooperation from Educational Institution and Civil Societies-** Cooperation can be sought from educational Institution and civil societies for giving wide publicity to the election related information to the general public and other stakeholders.
11. **Media Centre-** Effort should be made for awareness among the voters, political parties and other stakeholder through media center about election system including use of EVM/VVPAT.
12. **MCMC/DEMC-** ECI instruction contained in letters No. 491/MCMC/2014/Communication dated 24th March, 2014 provides that all registered political parties will approach the Media Certification and Monitoring Committees (MCMCs) at District and State level, as the case may be, for pre-certification of their political advertisements proposed to be issued on electronic media. The Commission has directed to ensure strict compliance of its instructions contained in above said letter.
13. **Control Room** – The 24x7 Control room at district level must be activated immediately and sufficient deployment of manpower and other logistics be ensured by the DEO/CEO. A Control Room with Complaint Monitoring Centre would also be set up at ECI Secretariat during the entire election process.

Yours faithfully,


(R.K. SRIVASTAVA)

SENIOR PRINCIPAL SECRETARY